

ग्वालियर-चम्बल सम्भाग में सरकारी औद्योगिक एवं व्यावसायिक नीतियों तथा योजनाओं के प्रति उद्यमियों की जागरूकता एवं व्यवसायिक विकास पर उनका प्रभाव: एक अनुभवजन्य अध्ययन

रोहित करैया¹ डॉ. मेघना शर्मा²

1. शोधार्थी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

2. सहायक प्रध्यापक एवं विभागाध्यक्षा वाणिज्य विभाग, महाराजा मान सिंह महाविद्यालय, ग्वालियर

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन “ग्वालियर-चम्बल सम्भाग में सरकारी औद्योगिक एवं व्यावसायिक नीतियों तथा योजनाओं के प्रति उद्यमियों की जागरूकता एवं व्यवसायिक विकास पर उनका प्रभाव: एक अनुभवजन्य अध्ययन” विषय पर आधारित है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ग्वालियर-चम्बल सम्भाग में उद्यमियों के बीच विभिन्न सरकारी औद्योगिक एवं व्यावसायिक नीतियों तथा योजनाओं के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना तथा इस जागरूकता के व्यवसाय एवं उद्योगों के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना है। सरकारी योजनाएँ वित्तीय सहायता, ऋण सुविधा, तकनीकी उन्नयन, कौशल विकास, विपणन सहायता तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के माध्यम से व्यवसायिक विकास को गति प्रदान करती हैं। हालांकि, इन योजनाओं की प्रभावशीलता काफी हद तक उद्यमियों की जानकारी और योजनाओं तक उनकी पहुँच पर निर्भर करती है।

अध्ययन में 200 उद्यमियों से संरचित प्रश्नावली के माध्यम से प्राथमिक आँकड़े एकत्रित किए गए। अध्ययन में प्रतिशत विश्लेषण, सहसंबंध एवं प्रतिगमन जैसी सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया गया। परिणामों से पता चला कि 49 प्रतिशत उत्तरदाता सरकारी औद्योगिक एवं व्यावसायिक योजनाओं के प्रति अधिक या बहुत अधिक जागरूक हैं, जबकि 26 प्रतिशत की जागरूकता मध्यम तथा 25 प्रतिशत की जागरूकता कम या बहुत कम पाई गई। सरकारी योजनाओं की जानकारी के प्रमुख स्रोतों में सरकारी विभाग, इंटरनेट एवं सामाजिक माध्यम तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ प्रमुख रहे। सहसंबंध विश्लेषण में सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता एवं व्यवसायिक विकास के मध्य 0.674 का धनात्मक संबंध पाया गया। प्रतिगमन विश्लेषण में $R^2 = 0.482$ प्राप्त हुआ, जिससे संकेत मिलता है कि व्यवसायिक विकास में लगभग 48.2 प्रतिशत परिवर्तन अध्ययन में सम्मिलित जागरूकता संबंधी कारकों द्वारा समझाया जा सकता है। योजना जागरूकता का मानकीकृत गुणांक 0.42 रहा, जो इसे व्यवसायिक विकास का महत्वपूर्ण प्रभावकारी कारक दर्शाता है।

अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी नीतियों एवं योजनाओं के प्रति बेहतर जागरूकता उद्यमियों को उपलब्ध सरकारी सुविधाओं तक पहुँच बनाने तथा व्यवसायिक विकास को बढ़ाने में सहायता करती है। अतः योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, डिजिटल सूचना व्यवस्था, सरल आवेदन प्रक्रिया तथा सरकारी विभागों एवं वित्तीय संस्थाओं के मध्य बेहतर समन्वय आवश्यक है।

प्रमुख शब्द: सरकारी नीतियाँ, सरकारी योजनाएँ, उद्यमी जागरूकता, व्यवसायिक विकास, औद्योगिक विकास, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, ग्वालियर-चम्बल सम्भाग, अनुभवजन्य अध्ययन।

1. प्रस्तावना

व्यापार और उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण हैं। औद्योगिक विकास केवल उत्पादन और आय में वृद्धि तक सीमित नहीं रहता; यह उद्यमिता का विकास, रोजगार के अवसरों का सृजन, स्थानीय संसाधनों का उपयोग, क्षेत्रीय असमानताओं में कमी और

जीवन स्तर में सुधार को भी प्रभावित करता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था का आधार विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम हैं। इन उद्यमों के माध्यम से स्थानीय संसाधनों और सीमित पूंजी का उपयोग करके व्यापक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ महत्वपूर्ण हैं।

सरकार वर्तमान में उद्यमिता को बढ़ावा देने, नए व्यवसायों की स्थापना, मौजूदा उद्योगों का विस्तार, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, कौशल विकास, विपणन सहायता और रोजगार सृजन के लिए कई नीतियाँ और योजनाएँ बना रही है। योजनाओं का मूल उद्देश्य उद्यमियों और व्यवसायियों को वित्तीय, तकनीकी, प्रबंधकीय तथा बाजार संबंधी अवरोधों से बचाना है। सरकारी सहायता उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने और मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करती है। यही कारण है कि सरकारी नीतियाँ केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं हैं, बल्कि उद्यमिता के लिए एक अनुकूल वातावरण भी बनाती हैं। यद्यपि, किसी सरकारी योजना की उपलब्धता और वास्तविक लाभ प्राप्त करना दो अलग-अलग चरणों से गुजरना चाहिए। संबंधित योजना की जानकारी होना, अपनी योग्यता को समझना और आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों से परिचित होना ही उद्यमी को योजना का लाभ उठाना संभव है। इसलिए योजना संबंधी जागरूकता सरकारी नीतियों की सफलता का एक महत्वपूर्ण माप बन जाती है। संभावित लाभार्थियों को किसी योजना के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होने पर योजना के लिए निर्धारित संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। दूसरी ओर, जागरूक उद्यमी सरकारी सुविधाओं को जानकर उनका उपयोग कर सकता है, जो उनके व्यवसाय की आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध हैं। इस मामले में ग्वालियर-चम्बल सम्भाग विशेष महत्व रखता है। यह मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण भौगोलिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में से एक है, जहाँ कृषि, व्यापार, विनिर्माण, सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, लघु उद्योगों और कई स्थानीय व्यवसाय चलते हैं। क्षेत्र में बहुत से उद्यमी सीमित धन, स्थानीय बाजार और पारंपरिक उद्यमशीलता पर निर्भर हैं। सरकारी योजनाएँ उद्यमियों को मदद कर सकती हैं और उनके व्यवसाय को बढ़ावा दे सकती हैं। वास्तविक लाभ, हालांकि, योजनाओं की जानकारी, सरकारी कार्यालयों तक पहुँच, दस्तावेजी आवश्यकताओं, वित्तीय संस्थाओं से समन्वय जैसे विषयों से प्रभावित हो सकता है। ग्वालियर-चम्बल सम्भाग में सरकारी नीतियों और योजनाओं का अध्ययन भी आवश्यक है क्योंकि विभिन्न उद्यमों पर नीतियों का प्रभाव क्षेत्रीय स्तर पर अलग-अलग हो सकता है। स्थापित उद्योगों को सरकारी धन या तकनीकी सहायता मिल सकती है ताकि वे अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें। दूसरी ओर, नए उद्यमी सरकारी धन या तकनीकी सहायता से व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। निर्माण कंपनियों के लिए आधारभूत संरचना और तकनीकी सुधार अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए ऋण सुविधा महत्वपूर्ण हो

सकती है। इसलिए, केवल सरकारी व्यय या योजनाओं की संख्या के आधार पर उनकी प्रभावशीलता का आकलन पर्याप्त नहीं है; साथ ही उद्यमों की वास्तविक जागरूकता और उनके परिणामों का अध्ययन भी आवश्यक है।

इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनुभवजन्य रूप से उद्यमियों की सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता का स्तर मापन है। जागरूकता को केवल इस आधार पर नहीं देखा गया कि उद्यमी ने किसी योजना का नाम सुना है; इसमें योजना की गुणवत्ता, आवेदन प्रक्रिया, उपलब्ध वित्तीय सहायता और अन्य सरकारी सुविधाओं की जानकारी भी शामिल है। इससे उद्यमियों तक सरकारी नीतियों की सूचना किस प्रकार पहुँच रही है और वे इसका उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं, यह समझने में सहायता मिलती है। व्यवसायिक विकास और जागरूकता के बीच संबंध की जांच दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। व्यवसाय के विस्तार, निवेश में वृद्धि, उत्पादन और बिक्री में वृद्धि, रोजगार सृजन और लाभप्रदता जैसे संकेत व्यवसायिक विकास को बता सकते हैं। यदि व्यवसायिक विकास और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता के बीच एक सकारात्मक संबंध पाया जाता है, तो इसका अर्थ है कि सूचना और जागरूकता की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके विपरीत, अधिक जागरूकता के बावजूद व्यवसायिक विकास कम होता है, तो यह संकेत कर सकता है कि समस्या सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है; यह योजना की पहुँच, प्रशासनिक कार्य, वित्तीय संस्थाओं की भूमिका या अन्य संरचनात्मक बाधाओं से भी संबंधित है।

सरकारी सहायता, एमएसएमई विकास, वित्तीय पहुँच, उद्यमिता और सरकारी नीतियों के प्रभाव पर पूर्ववर्ती अध्ययनों में पर्याप्त चर्चा की गई है। विभिन्न अध्ययनों ने दिखाया है कि संस्थागत समर्थन और वित्तीय सहायता छोटे और मध्यम उद्यमों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। ग्वालियर-चम्बल सम्भाग जैसे विशिष्ट क्षेत्र में उद्यमियों की सरकारी औद्योगिक एवं व्यावसायिक योजनाओं के प्रति जागरूकता और उनके व्यवसायिक विकास से संबंध का अनुभवजन्य अध्ययन बहुत कम है। यही इस अध्ययन की मुख्य शोध आवश्यकता है। ग्वालियर-चम्बल सम्भाग के उद्यमियों को मुख्यधारा में रखते हुए इस अध्ययन में सरकारी औद्योगिक और व्यावसायिक नीतियों और योजनाओं के प्रति उद्यमियों की जागरूकता का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, अध्ययन जागरूकता का व्यवसाय और उद्योगों के विकास पर कितना प्रभाव पड़ता है। इस उद्देश्य से प्राथमिक आँकड़ों के आधार पर सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है, ताकि अध्ययन को अनुभवजन्य और विश्लेषणात्मक बनाया जा

सके, वर्णनात्मक नहीं। यह अध्ययन स्थानीय उद्यमियों, सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थाओं और नीति-निर्माताओं को लाभ दे सकता है और क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की पहुँच और प्रभावशीलता को बेहतर बना सकता है।

1. अध्ययन के उद्देश्य

- ग्वालियर-चम्बल सम्भाग में सरकार की विभिन्न औद्योगिक एवं व्यावसायिक नीतियों तथा योजनाओं के प्रति उद्यमियों की जागरूकता का अध्ययन करना।
- सरकारी नीतियों एवं योजनाओं के प्रति उद्यमियों की जागरूकता का व्यवसाय एवं उद्योगों के विकास पर प्रभाव का विश्लेषण करना।

2. साहित्य का समीक्षात्मक अध्ययन

शर्मा (2022) शर्मा ने आर्थिक व्यवधानों के संदर्भ में एमएसएमई के लिए सरकारी नीतिगत पहलों के प्रभाव का अध्ययन किया। शोध में यह पाया गया कि सरकारी सहायता योजनाएँ छोटे उद्यमों को संकट की परिस्थितियों में स्थायित्व प्रदान करने में उपयोगी रही हैं। हालाँकि, योजनाओं का प्रभाव उनकी पहुँच और कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर निर्भर करता है। यह निष्कर्ष वर्तमान अध्ययन के दूसरे उद्देश्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।

मुखर्जी एवं मुखर्जी (2022) मुखर्जी एवं मुखर्जी ने भारतीय छोटे एवं मध्यम उद्यमों की वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भागीदारी का अध्ययन किया। शोध में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, तकनीकी उन्नयन, बाजार तक पहुँच तथा संस्थागत वातावरण को उद्यमों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया। अध्ययन यह संकेत देता है कि सरकारी नीतियाँ उद्यमों को व्यापक बाजार से जोड़ने में सहायक हो सकती हैं।

मजीद एवं मुश्ताक (2022) मजीद एवं मुश्ताक ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के संदर्भ में भारतीय एमएसएमई क्षेत्र पर नीतिगत हस्तक्षेपों का अध्ययन किया। अध्ययन में यह संकेत दिया गया कि सरकारी नीतियाँ एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन प्रदान कर सकती हैं, लेकिन नीतियों की वास्तविक प्रभावशीलता उनके उचित क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक पहुँच पर निर्भर करती है।

चुंडक्कडन, नटराजन एवं ससीधरन (2022) चुंडक्कडन एवं सहयोगियों ने छोटे उद्यमों पर वित्तीय बाधाओं और सरकारी सहायता के प्रभाव का अनुभवजन्य अध्ययन किया। शोध से पता

चला कि वित्तीय बाधाएँ छोटे उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण समस्या हैं और सरकारी सहायता ऐसी बाधाओं को कम करने में सहायक हो सकती है। यह अध्ययन वर्तमान शोध में सरकारी योजनाओं की जागरूकता और व्यवसायिक विकास के संबंध को समझने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।

सिंह (2024) सिंह ने भारत में एमएसएमई के विकास में सरकारी सहायता योजनाओं की भूमिका का अध्ययन किया। अध्ययन में सरकारी सहायता को एमएसएमई विकास का महत्वपूर्ण समर्थनकारी तत्व माना गया। साथ ही यह संकेत दिया गया कि योजनाओं की जानकारी और उपलब्ध सहायता तक पहुँच में अंतर होने के कारण सभी उद्यमी समान रूप से लाभ प्राप्त नहीं कर पाते।

तालकर, शेख एवं खान (2024) तालकर एवं सहयोगियों ने मुंबई के एमएसएमई में सरकारी वित्तीय योजनाओं की जागरूकता, पहुँच एवं धारणा का अध्ययन किया। अध्ययन वर्तमान शोध के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें केवल सरकारी सहायता की उपलब्धता नहीं, बल्कि उद्यमियों की योजना संबंधी जागरूकता और उनकी पहुँच को भी अध्ययन का हिस्सा बनाया गया।

सैनी, मल्होत्रा एवं भूषण (2024) सैनी एवं सहयोगियों ने महिला उद्यमियों पर सरकारी सहायता कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन किया। परिणामों से पता चला कि सरकारी सहायता उद्यमिता और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सहायक हो सकती है। अध्ययन ने यह भी संकेत दिया कि सरकारी कार्यक्रमों का प्रभाव लाभार्थियों की पहुँच और उपयोग पर निर्भर करता है।

फजारिका, ट्रैप्सिलावती एवं सोफा (2024) फजारिका एवं सहयोगियों ने विकसित एवं विकासशील देशों में छोटे एवं मध्यम उद्यमों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की व्यवस्थित समीक्षा की। अध्ययन में वित्तीय संसाधन, तकनीकी क्षमता, बाजार, संस्थागत वातावरण और सरकारी समर्थन को उद्यम विकास के प्रमुख निर्धारकों में शामिल किया गया।

नीति आयोग (2025) नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता संबंधी रिपोर्ट में भारतीय एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, वित्तीय पहुँच, तकनीकी क्षमता, बाजार विस्तार तथा नीतिगत समर्थन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। यह रिपोर्ट वर्तमान अध्ययन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि

यह सरकारी नीतियों को उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता एवं विकास से जोड़ती है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (2025) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में विभिन्न सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता कार्यक्रमों, उद्यमिता विकास, तकनीकी केंद्रों तथा एमएसएमई को उपलब्ध संस्थागत समर्थन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह स्रोत वर्तमान अध्ययन में सरकारी योजनाओं की पृष्ठभूमि तथा उनके स्वरूप को समझने के लिए महत्वपूर्ण द्वितीयक आधार प्रदान करता है।

3. अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन "ग्वालियर-चम्बल सम्भाग में सरकारी औद्योगिक एवं व्यावसायिक नीतियों तथा योजनाओं के प्रति उद्यमियों की जागरूकता एवं व्यवसायिक विकास पर उनका प्रभाव: एक अनुभवजन्य अध्ययन" विषय पर आधारित है। अध्ययन का स्वरूप वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं अनुभवजन्य है। इसका उद्देश्य सरकारी औद्योगिक एवं व्यावसायिक नीतियों तथा योजनाओं के प्रति उद्यमियों की जागरूकता का मापन करना तथा यह निर्धारित करना है कि जागरूकता व्यवसाय एवं उद्योगों के विकास से किस प्रकार संबंधित है।

4.1 अध्ययन की जनसंख्या एवं नमूना

अध्ययन की जनसंख्या में ग्वालियर-चम्बल सम्भाग के विभिन्न जिलों में व्यवसाय एवं औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े उद्यमियों को सम्मिलित किया गया। अध्ययन के लिए 200 उद्यमियों का चयन किया गया। नमूने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के व्यवसाय तथा विभिन्न व्यापारिक एवं औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया।

4.2 आँकड़ों का संकलन

प्राथमिक आँकड़ों संरचित प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित किए गए। प्रश्नावली में उत्तरदाताओं की सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता, योजनाओं की जानकारी के स्रोत, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी तथा व्यवसायिक विकास से संबंधित प्रश्न सम्मिलित किए गए।

द्वितीयक आँकड़ों के लिए सरकारी रिपोर्टें, एमएसएमई संबंधी दस्तावेजों, औद्योगिक नीति दस्तावेजों तथा पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों का उपयोग किया गया।

4.3 मापन मापनी

जागरूकता एवं व्यवसायिक विकास से संबंधित कथनों को पाँच-बिंदु लिंकर्ट मापनी पर मापा गया:

अंक	प्रतिक्रिया
1	पूर्णतः असहमत
2	असहमत
3	न तो सहमत, न असहमत
4	सहमत
5	पूर्णतः सहमत

4.4 अध्ययन के प्रमुख चर

स्वतंत्र चर: सरकारी औद्योगिक एवं व्यावसायिक नीतियों तथा योजनाओं के प्रति जागरूकता।

आश्रित चर: व्यवसाय एवं उद्योगों का विकास।

व्यवसायिक विकास को व्यवसाय विस्तार, निवेश, बिक्री, उत्पादन, रोजगार तथा लाभप्रदता जैसे संकेतकों के आधार पर मापा गया।

4.5 सांख्यिकीय विश्लेषण

प्राथमिक आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, औसत, मानक विचलन, सहसंबंध तथा प्रतिगमन विश्लेषण के माध्यम से किया गया। अध्ययन की परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए सांख्यिकीय महत्व के स्तर को 5 प्रतिशत रखा गया।

4. परिणाम एवं विश्लेषण

4.1 उत्तरदाताओं की सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता

सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का पहला आधार यह है कि संभावित लाभार्थी उन योजनाओं के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। इसलिए सबसे पहले उत्तरदाताओं की योजना-जागरूकता का विश्लेषण किया गया।

तालिका 5.1 सरकारी औद्योगिक एवं व्यावसायिक योजनाओं के प्रति उत्तरदाताओं की जागरूकता

जागरूकता का स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
बहुत अधिक	42	21%
अधिक	56	28%
मध्यम	52	26%
कम	32	16%
बहुत कम	18	9%
कुल	200	100%



चित्र 5.1 सरकारी औद्योगिक एवं व्यावसायिक योजनाओं के प्रति उत्तरदाताओं की जागरूकता

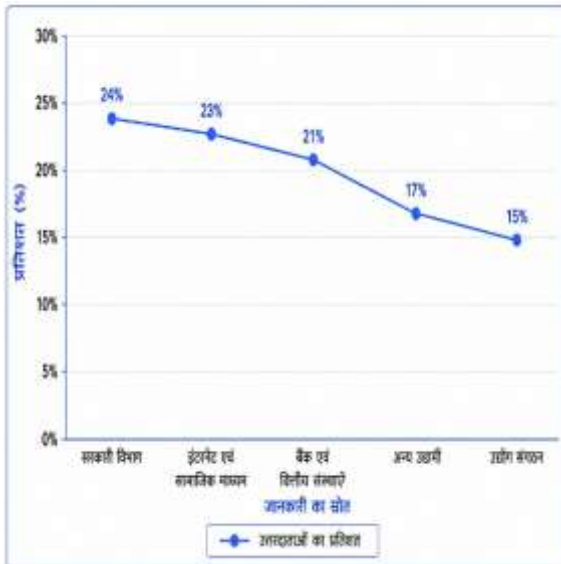
व्याख्या: तालिका 5.1 और चित्र 5.1 से स्पष्ट है कि 49 प्रतिशत उत्तरदाता सरकारी औद्योगिक एवं व्यावसायिक योजनाओं के प्रति अधिक अथवा बहुत अधिक जागरूक हैं। 26 प्रतिशत उत्तरदाताओं की जागरूकता मध्यम स्तर की है, जबकि 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं में जागरूकता कम अथवा बहुत कम पाई गई। यह परिणाम दर्शाता है कि लगभग आधे उद्यमियों तक सरकारी योजनाओं की पर्याप्त जानकारी पहुँच रही है, लेकिन एक चौथाई उद्यमियों में जागरूकता का निम्न स्तर पाया जाना नीति-प्रसार की चुनौती को दर्शाता है। अतः योजनाओं की उपलब्धता के साथ-साथ उनकी जानकारी को स्थानीय उद्यमियों तक पहुँचाना आवश्यक है।

4.2 सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के स्रोत

उद्यमियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी किन माध्यमों से प्राप्त होती है, इसका विश्लेषण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभावी सूचना-प्रसार योजना की पहुँच को बढ़ा सकता है।

तालिका 5.2 सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत

जानकारी का स्रोत	आवृत्ति	प्रतिशत
सरकारी विभाग	48	24%
इंटरनेट एवं सामाजिक माध्यम	46	23%
बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ	42	21%
अन्य उद्यमी	34	17%
उद्योग संगठन	30	15%
कुल	200	100%



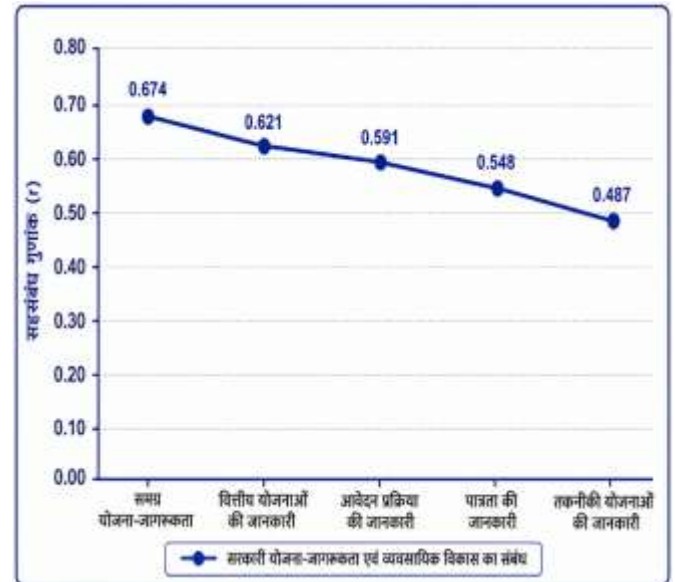
चित्र 5.2 सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत

5.3 योजना-जागरूकता एवं व्यवसायिक विकास के मध्य संबंध

अध्ययन के दूसरे उद्देश्य के अंतर्गत यह परीक्षण किया गया कि सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता और व्यवसायिक विकास के मध्य कोई महत्वपूर्ण सांख्यिकीय संबंध मौजूद है अथवा नहीं।

तालिका 5.3 सरकारी योजना-जागरूकता एवं व्यवसायिक विकास के मध्य सहसंबंध

चर	व्यवसायिक विकास के साथ सहसंबंध
समग्र योजना-जागरूकता	0.674
पात्रता की जानकारी	0.548
आवेदन प्रक्रिया की जानकारी	0.591
वित्तीय योजनाओं की जानकारी	0.621
तकनीकी योजनाओं की जानकारी	0.487



तालिका 5.3 से स्पष्ट है कि समग्र सरकारी योजना-जागरूकता और व्यवसायिक विकास के मध्य 0.674 का धनात्मक सहसंबंध पाया गया। यह अपेक्षाकृत मजबूत सकारात्मक संबंध है। इसका अर्थ है कि सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ व्यवसायिक विकास में भी वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

वित्तीय योजनाओं की जानकारी का सहसंबंध 0.621 रहा, जो दर्शाता है कि वित्तीय सहायता से संबंधित जानकारी व्यवसायिक विकास के साथ महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। तकनीकी योजनाओं की जानकारी का सहसंबंध 0.487 रहा, जो अन्य कारकों की तुलना में कम होने के बावजूद सकारात्मक है।

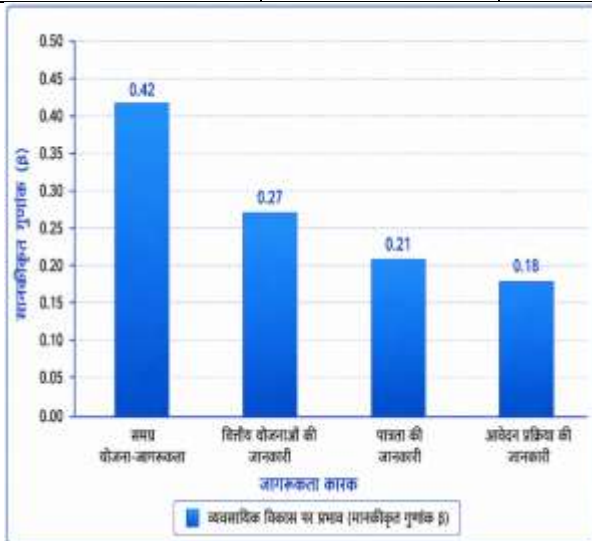
5.4 जागरूकता का व्यवसायिक विकास पर प्रभाव

सहसंबंध के अतिरिक्त यह जानना आवश्यक है कि योजना-जागरूकता व्यवसायिक विकास में होने वाले परिवर्तन को किस सीमा तक स्पष्ट करती है। इसके लिए प्रतिगमन विश्लेषण किया गया।

तालिका 5.4 सरकारी योजना-जागरूकता का व्यवसायिक विकास पर प्रतिगमन प्रभाव

स्वतंत्र चर	मानकीकृत गुणांक (β)	महत्व स्तर
समग्र योजना-जागरूकता	0.42	0.000
वित्तीय योजनाओं की जानकारी	0.27	0.001

पात्रता की जानकारी	0.21	0.003
आवेदन प्रक्रिया की जानकारी	0.18	0.008
R^2	0.482	—



चित्र 5.4 विभिन्न जागरूकता कारकों का व्यवसायिक विकास पर प्रभाव

व्याख्या: प्रतिगमन विश्लेषण में $R^2 = 0.482$ प्राप्त हुआ। इसका अर्थ है कि व्यवसायिक विकास में लगभग 48.2 प्रतिशत परिवर्तन अध्ययन में सम्मिलित जागरूकता संबंधी कारकों द्वारा समझाया जा सकता है। समग्र योजना-जागरूकता का मानकीकृत गुणांक 0.42 रहा, जो सभी कारकों में सर्वाधिक है। इससे संकेत मिलता है कि सरकारी योजनाओं के प्रति समग्र जागरूकता व्यवसायिक विकास का प्रमुख प्रभावकारी कारक है।

वित्तीय योजनाओं की जानकारी का गुणांक 0.27 रहा, जबकि पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के गुणांक क्रमशः 0.21 और 0.18 रहे। इससे स्पष्ट होता है कि केवल योजना के बारे में सामान्य जानकारी पर्याप्त नहीं है; उद्यमी को योजना की पात्रता तथा आवेदन प्रक्रिया की भी जानकारी होना आवश्यक है।

5.5 परिकल्पना परीक्षण

प्राप्त सहसंबंध एवं प्रतिगमन परिणामों के आधार पर अध्ययन की दोनों परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया।

परिकल्पना	परिणाम	निष्कर्ष
H ₀₁ : जागरूकता एवं व्यवसायिक विकास में महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।	0.674 का धनात्मक संबंध	अस्वीकृत
H ₀₂ : जागरूकता का व्यवसायिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।	$R^2 = 0.482$; $\beta = 0.42$	अस्वीकृत

परिणामों से दोनों शून्य परिकल्पनाएँ अस्वीकृत होती हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ग्वालियर-चम्बल सम्भाग में सरकारी औद्योगिक एवं व्यावसायिक नीतियों तथा योजनाओं के प्रति उद्यमियों की जागरूकता का व्यवसाय एवं उद्योगों के विकास के साथ महत्वपूर्ण एवं धनात्मक संबंध है तथा जागरूकता व्यवसायिक विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है।

5. चर्चा

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य ग्वालियर-चम्बल सम्भाग में सरकारी औद्योगिक एवं व्यावसायिक नीतियों तथा योजनाओं के प्रति उद्यमियों की जागरूकता का अध्ययन करना तथा इस जागरूकता के व्यवसाय एवं उद्योगों के विकास पर प्रभाव का विश्लेषण करना था। अध्ययन में 200 उद्यमियों से प्राप्त प्राथमिक आँकड़ों के आधार पर किए गए विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि सरकारी योजनाओं की जानकारी और व्यवसायिक विकास के मध्य सकारात्मक संबंध विद्यमान है। जागरूकता के विश्लेषण से पता चला कि 21 प्रतिशत उत्तरदाता सरकारी योजनाओं के प्रति बहुत अधिक तथा 28 प्रतिशत अधिक जागरूक थे। इस प्रकार कुल 49 प्रतिशत उत्तरदाता उच्च स्तर की जागरूकता रखते हैं। वहीं 26 प्रतिशत उत्तरदाताओं की जागरूकता मध्यम तथा 25 प्रतिशत की जागरूकता कम या बहुत कम पाई गई। यह स्थिति बताती है कि सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार होने के बावजूद सभी उद्यमियों तक समान स्तर पर जानकारी नहीं पहुँच रही है। विशेष रूप से छोटे एवं सीमित संसाधनों वाले उद्यमियों के लिए योजना संबंधी जानकारी प्राप्त करना अभी भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

योजनाओं की जानकारी के स्रोतों का विश्लेषण करने पर सरकारी विभाग 24 प्रतिशत के साथ प्रमुख स्रोत रहे, जबकि इंटरनेट एवं सामाजिक माध्यम 23 प्रतिशत तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ 21 प्रतिशत रहे। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी संस्थाओं की प्रत्यक्ष

भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन डिजिटल माध्यम भी तेजी से प्रभावशाली सूचना स्रोत बन रहे हैं। अतः सरकारी योजनाओं के प्रचार में पारंपरिक एवं डिजिटल दोनों माध्यमों का समन्वित उपयोग अधिक प्रभावी हो सकता है।

अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम सरकारी योजना-जागरूकता एवं व्यवसायिक विकास के मध्य प्राप्त 0.674 के धनात्मक सहसंबंध से संबंधित है। यह परिणाम दर्शाता है कि जिन उद्यमियों को सरकारी योजनाओं की बेहतर जानकारी है, उनमें व्यवसायिक विकास की प्रवृत्ति भी अपेक्षाकृत अधिक है। वित्तीय योजनाओं की जानकारी का 0.621 का सहसंबंध यह संकेत देता है कि वित्तीय सहायता से संबंधित जागरूकता व्यवसाय विस्तार में विशेष महत्व रखती है। प्रतिगमन विश्लेषण में $R^2 = 0.482$ प्राप्त हुआ, जिससे संकेत मिलता है कि व्यवसायिक विकास में 48.2 प्रतिशत परिवर्तन अध्ययन में शामिल जागरूकता संबंधी कारकों द्वारा समझाया जा सकता है। समग्र योजना-जागरूकता का मानकीकृत गुणांक 0.42 रहा, जो अन्य कारकों की तुलना में अधिक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल सरकारी सहायता की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं है; उसके बारे में उद्यमियों की जानकारी भी व्यवसायिक परिणामों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है।

6. निष्कर्ष

अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ग्वालियर-चम्बल सम्भाग में सरकारी औद्योगिक एवं व्यावसायिक नीतियों तथा योजनाओं के प्रति उद्यमियों की जागरूकता व्यवसाय एवं उद्योगों के विकास से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है। उच्च जागरूकता वाले उद्यमियों के लिए सरकारी सहायता, वित्तीय सुविधाओं तथा अन्य संस्थागत अवसरों तक पहुँच बनाने की संभावना अधिक दिखाई देती है। अध्ययन के दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए यह पाया गया कि सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता का स्तर व्यवसायिक विकास के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ा है। इसलिए सरकारी विभागों को स्थानीय उद्यमियों के लिए नियमित जागरूकता शिविर, सरल भाषा में योजना संबंधी जानकारी, डिजिटल सूचना प्रणाली तथा सहायता केंद्र विकसित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही बैंकों, उद्योग संगठनों एवं सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। इससे योजनाओं की जानकारी और वास्तविक लाभ के बीच की दूरी कम होगी तथा ग्वालियर-चम्बल

सम्भाग में व्यवसाय एवं उद्योगों के अधिक समावेशी एवं सतत विकास को प्रोत्साहन मिल सकेगा।

संदर्भ सूची

1. चुण्डक्कडन, आर., एवं ससीधरन, एस. (2020). वित्तीय बाधाएँ, सरकारी सहायता और फर्म नवाचार: विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से अनुभवजन्य साक्ष्य। *नवाचार एवं विकास*, 10(3), 279–301.
<https://doi.org/10.1080/2157930X.2019.1594680>
2. चुण्डक्कडन, आर., नटराजन, आर. आर., एवं ससीधरन, एस. (2022). कोविड-19 के दौरान लघु फर्मों: वित्तीय बाधाएँ एवं सरकारी सहायता की भूमिका। *इकोनॉमिक नोट्स*, 51, e12206. <https://doi.org/10.1111/ecno.12206>
3. चुण्डक्कडन, आर., एवं ससीधरन, एस. (2023). महामारी संकट के दौरान सरकारी सहायता, ई-वाणिज्य और फर्म नवाचार की भूमिका। *इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी*, 78, 904–913.
<https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.04.021>
4. जोशी, के., भारती, आर., एवं डांगवाल, आर. सी. (2021). उत्तराखंड में लघु उद्यमियों की सरकारी सहायता के प्रति धारणा। *लघु उद्यम विकास, प्रबंधन एवं विस्तार पत्रिका*, 48(1), 28–46.
<https://doi.org/10.1177/09708464211054881>
5. तलकर, पी. आर., शेख, एस., एवं खान, ए. ए. (2024). मुंबई में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर सरकारी वित्तीय योजनाओं की जागरूकता, पहुँच एवं धारणा का अध्ययन। *शोध एवं वित्तीय प्रबंधन का अंतरराष्ट्रीय जर्नल*.
<https://doi.org/10.33545/26175754.2021.v4.i1a.96>
6. सजना, वी., एवं धर्मराज, ए. (2024). सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के उद्यमियों में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की जागरूकता: एक अन्वेषणात्मक अध्ययन। *भारतीय सूचना स्रोत एवं सेवा पत्रिका*, 14(3), 115–122.
<https://doi.org/10.51983/ijiss-2024.14.3.16>
7. साकिब, एम. एन., एवं रहमान, एम. एम. (2024). कोविड-19 के प्रभाव को कम करने में सरकारी नीतिगत हस्तक्षेप एवं लघु तथा मध्यम उद्यम: व्यवस्थित साहित्य समीक्षा एवं ग्रंथसूची विश्लेषण। *फ्यूचर बिजनेस जर्नल*, 10(1), 1–11.
<https://doi.org/10.1186/s43093-024-00346-0>

8. सिंह, एन., मुंजाल, एस., कुंडू, एस., एवं रंगराजन, के. (2023). छोटे उद्यमों के मंच-आधारित अंतरराष्ट्रीयकरण में सरकारी नीति की भूमिका। *मैनेजमेंट इंटरनेशनल रिव्यू*, 63(1), 91–115. <https://doi.org/10.1007/s11575-022-00492-z>
9. कूकर, के., एवं मेहता, एम. सी. (2022). भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्थान के लिए चयनित सरकारी योजनाओं एवं नीतियों की समीक्षा। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड मैनेजमेंट*, 5(4), 16–19.
10. जैकब, ए., हरिणी, एम., नोआ, आर. एस., प्रभा, डी. डी., एवं मथिपुरानी, वी. बी. (2021). महिला उद्यमियों में भारतीय सरकारी एमएसएमई योजनाओं के प्रति जागरूकता का अध्ययन। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट*, 4(1), 42–46. <https://doi.org/10.33545/26175754.2021.v4.i1a.96>
11. मुखर्जी, एस. (2018). वैश्वीकरण के युग में भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की चुनौतियाँ। *जर्नल ऑफ ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च*, 8, 28.
12. त्रिपाठी, आई. जी., एवं कुमार, पी. (2019). भारतीय एमएसएमई निर्यातकों की चुनौतियाँ: एक समीक्षा। *लघु उद्यम विकास, प्रबंधन एवं विस्तार पत्रिका*, 46(3). <https://doi.org/10.1177/0970846419871113>
13. कौर, जी. (2017). आर्थिक सुधार एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च*, 5(5). <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v5.i5.2017.1875>
14. बेलघितार, वाई., मोरो, ए., एवं राडिच, एन. (2022). जब कठिन समय सबसे कठिन संकट बन जाए: कोविड-19 के दौरान एसएमई पर सरकारी नीतियों का प्रभाव। *स्मॉल बिजनेस इकोनॉमिक्स*, 58, 943–961. <https://doi.org/10.1007/s11187-021-00510-8>
15. जुलु-चिसांगा, एस., चाबाला, एम., एवं मंडावा-ब्रे, बी. (2021). विकासशील अर्थव्यवस्था में एसएमई प्रदर्शन पर सरकारी सहायता, अंतर-फर्म सहयोग एवं फर्म संसाधनों के विभेदक प्रभाव। *जर्नल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इमर्जिंग इकोनॉमीज*, 13(2), 175–195. <https://doi.org/10.1108/JEEE-07-2019-0105>
16. चुण्डक्कडन, आर., एवं ससीधरन, एस. (2020). फर्म आकार, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार: भारत से साक्ष्य। *एशियन रिसर्च पॉलिसी*, 10(2), 39–46.
17. चुण्डक्कडन, आर., एवं ससीधरन, एस. (2020). केंद्रीय बैंक की तरलता उपलब्धता एवं फर्मों की वित्तीय बाधाएँ। *इकोनॉमिक मॉडलिंग*, 89, 245–255.
18. प्रसन्नाथ, वी., अधिकारी, पी., ग्रोनम, एस., एवं माइल्स, एम. पी. (2024). सरकारी सहायता नीतियाँ, उद्यमशील अभिविन्यास एवं लघु तथा मध्यम उद्यमों का प्रदर्शन। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस*.
19. दास, ए., एवं पाल, बी. (2022). महामारी के बाद ग्रामीण उद्यमियों की स्थिति: पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के चयनित क्षेत्रों का अध्ययन। *साउथ एशियन जर्नल ऑफ सोशल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स*, 15(3), 9–15. <https://doi.org/10.9734/sajsse/2022/v15i330406>
20. सैनी, आर., मल्होत्रा, एम., एवं भूषण, एस. (2024). महिला उद्यमिता एवं सरकारी सहायता कार्यक्रमों की भूमिका का अध्ययन। *उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय अध्ययन*.
21. शुक्ला, आर., एवं शंकर, आर. (2024). छोटे एवं मध्यम उद्यमों में स्मार्ट विनिर्माण तकनीकों के कार्यान्वयन में सरकारी सहायता की भूमिका। *लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता अध्ययन*.
22. यादव, आर., एवं शर्मा, एस. (2021). भारत में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण संबंधी नीतिगत हस्तक्षेप एवं आर्थिक परिणाम। *भारतीय आर्थिक अध्ययन*.
23. कुमार, आर., एवं कुमार, एस. (2022). भारत में एमएसएमई विकास एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में सरकारी नीतियों की भूमिका। *भारतीय वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन पत्रिका*.
24. महेशकर, सी., एवं सोनी, आर. (2021). भारतीय एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियाँ एवं विकास की संभावनाएँ। *भारतीय लघु व्यवसाय अध्ययन पत्रिका*.
25. मोरी, के. वी. (2025). एमएसएमई के लिए सरकारी सहायता एवं औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र पर उसका प्रभाव। *इंटरनेशनल एजुकेशनल एप्लाइड साइंटिफिक रिसर्च जर्नल*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17045792>